

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 अग्रहायण, 1941 (श॰)

संख्या- 1050 राँची, गुरुवार, 19 दिसम्बर, 2019 (ई॰)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

17 दिसम्बर, 2019

संख्या--5/आरोप-1-18/2017-27385 (HRMS)-- श्री रवीन्द्र गगराई, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला-प0 सिंहभूम), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूँटी-सह-प्रभारी अधीक्षक, उपकारा, खूँटी के विरूद्ध कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-351/जेल, दिनांक 25.01.2017 द्वारा दिनांक 07.01.2017 को कारा तलाशी में कारा हस्तक नियम-615 में प्रतिबंधित आपित्तिजनक सामग्रियों की बरामदगी, कारा का उचित ढंग से पर्यवेक्षण नहीं करने तथा अपने अधीनस्थ कर्मियों पर पकड़ कमजोर रखने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-3799, दिनांक 22.03.2017 द्वारा श्री गगराई से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री गगराई के पत्रांक-442, दिनांक 18.04.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें कहा गया कि कारा में पदस्थापित कक्षपाल (भूतपूर्व सैनिक) श्री झगरू महतो द्वारा बंदियों से रूपये लेकर प्रतिबंधित सामग्रियाँ पहुँचाया गया था एवं श्री महतो द्वारा अपना दोष स्वीकार कर लिया गया है एवं श्री गगराई के प्रतिवेदन के आधार पर श्री महतो का अन्बंध समाप्त किया गया है।

श्री गगराई के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-7585, दिनांक 28.06.2017 द्वारा कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गयी तथा इसके लिए स्मारित भी किया गया। उक्त के आलोक में कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2341, दिनांक 07.08.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि मोबाईल बंदियों तक पहुँचाने के आरोपी कक्षपाल (भूतपूर्व सैनिक) श्री झगरू महतो का अनुबंध समाप्त किया गया है तथा तत्कालीन सहायक कारापाल (प्रभारी कारापाल) श्री प्रमोद कुमार को निन्दन की सजा दी गई है। श्री गगराई के विरूद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के मंतव्य के समीक्षोपरांत, श्री गगराई के विरूद्ध "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name	Decision of the Competent authority
	G.P.F. No.	
1	2	3
1	RAVINDERA GAGRAEE 20060400056	श्री रवीन्द्र गगराई, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूँटी-सह-प्रभारी अधीक्षक, उपकारा, खूँटी के विरूद्ध "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान, सरकार के संयुक्त सचिव। जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
